



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276632
CG-DL-E-30092026-276632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4979]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948

No. 4979]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितंबर, 2026

का.आ. 5185(अ).— पहचान साबित करने के लिए आधार संख्या का प्रयोग व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में सहायिकीयां, प्रसुविधाएं और सेवाएं पाने में समर्थ करता है, पहचान साबित करने के लिए कई प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता को खत्म करता है, प्रक्रियाओं को आसान बनाता है और पारदर्शिता और दक्षता का संवर्द्धन करता है:

और भारत सरकार (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त सरकार' कहा गया है) का सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त विभाग' कहा गया है) अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा (जिसे आगे 'उक्त योजना' कहा गया है) संचालन कर रहा है:

और उक्त स्कीम और उससे संबंधित जारी अनुदेशों और मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अधीन अनुसूचित जाति के छात्रों (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् 'फायदाग्राही' कहा गया है) को छात्रवृत्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त फायदा' कहा गया है) दी जाती है:

और उक्त स्कीम का व्यय भारत की संचित निधि से उपगत किया जाता है:

और उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग चाहता है कि उक्त सरकार, किसी फायदाग्राही को उक्त फायदा देने की शर्त के तौर पर उसकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए, यह अपेक्षा करे कि ऐसा फायदाग्राही अपना सत्यापन कराए,

या आधार संख्या होने का प्रमाण दे, या किसी व्यक्ति को आधार संख्या नहीं मिलने की दशा में, वह नामांकन के लिए आवेदन करे:

अतः अब, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अधीन, भारत सरकार निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

(1) उक्त स्कीम के अधीन उक्त फायदे का उपभोग करने के वांछनीय व्यक्ति को अधिप्रमाणन करवाना अपेक्षित होगा या आधार संख्या होने का प्रमाण देना होगा।

(2) ऐसे व्यक्ति को आधार संख्या नहीं दिए जाने की दशा में, उसे नामांकन के लिए आवेदन करना अपेक्षित होगा:

परंतु यदि वह व्यक्ति बालक हो, तो ऐसा आवेदन केवल उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक की सहमति से ही किया जाएगा।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के उपबंधों के अनुसार, उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग उन फायदाग्राहियों का नामांकन सुनिश्चित करेगा जिन्हें अभी तक नामांकित किया जाना है, या उचित तरीकों से उनके आधार ब्यौरों को अपडेट करेगा। जिसमें रजिस्ट्रार के साथ समन्वयन बिठाना, सुविधाजनक स्थानों पर नामांकन केन्द्र स्थापित करना या स्वतः रजिस्ट्रार बनकर नामांकन प्रसुविधाएं प्रदान करना शामिल है:

परंतु जब तक ऐसे फायदाग्राही को आधार संख्या नहीं मिल जाती, तब तक वह उक्त फायदा पाने के लिए अपनी पहचान साबित करने के लिए ऐसे निम्नलिखित दस्तावेज दिखा सकता है जिसका वह हकदार है और जो दिखाने के समय विधिमाम्य हैं; या, यदि उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा ऐसी पहचान के लिए उपलब्ध कराया गया या प्राधिकृत सॉफ्टवेयर, ऐसी पहचान के लिए, ऐसे दस्तावेजों के अंतर्वस्तु की साक्ष्य के रूप में जानकारी को संबंधित प्राधिकारियों के डेटाबेस से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अभिप्राप्त करने की सुविधा देता है जो उन्हें तैयार या बनाए रखते हैं, वह ऐसी जानकारी अभिप्राप्त करने के लिए अपनी सहमति दे सकता है, अर्थात्:—

18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक के लिए जिसे आधार संख्या नहीं दिया गया है:

(क) नामांकन केन्द्र पर प्रचालक द्वारा फायदाग्राही के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) हो; और

(ख) इस बात का प्रमाण देने के लिए कि फायदाग्राही 18 वर्ष से कम उम्र का बालक है, नीचे दिए गए दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज, अर्थात्:—

(i) फायदाग्राही के जन्म के संबंध में जन्म रजिस्टर में की गई प्रविष्टि से उद्धरण के रूप में, जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का 18) के अधीन जारी जन्म प्रमाण-पत्र;

(ii) भारतीय पासपोर्ट;

(iii) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंक-पत्र;

(iv) देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की दशा, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन इसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबद्ध राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत किसी बाल देख-रेख संस्था में रखा गया है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें उसकी जन्म की तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो; या

(v) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारत का विदेशी नागरिक कार्ड-धारक है, तो भारत का विदेशी नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह भारत का विदेशी नागरिक कार्ड धारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या भारत का दीर्घावधि वीजा के साथ वर्तमान में विधिमान्य या अवसन्नित विदेशी पासपोर्ट; या

(ग) माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध का प्रमाण देने के लिए, फायदाग्राही के फोटो वाले निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई भी एक, अर्थात्:—

(i) राशन कार्ड;

(ii) जाति प्रमाण-पत्र या अधिवास प्रमाण-पत्र, किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो राज्य सरकार का कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी हो और जिसका रैंक तहसीलदार के पद से कम का न हो;

(iii) किसी सरकारी अस्तित्व या पब्लिक सेक्टर उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत लोक सेवक या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया चिकित्सा या बीमा पहचान पत्र;

(iv) भारतीय पासपोर्ट;

(v) किसी मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10वीं कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12वीं कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंक-पत्र;

(vi) देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले किसी बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले किसी बालक की दशा में, जिसे किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (2016 का 2) के अधीन इसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबद्ध राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत किसी बाल देख-रेख संस्था में रखा गया है, ऐसी संस्था के प्रभारी व्यक्ति, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र जिसमें उसकी जन्म की तारीख विनिर्दिष्ट की गई का उल्लेख हो; या

(vii) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारत का विदेशी नागरिक कार्ड-धारक है, तो भारत का विदेशी नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह भारत का विदेशी नागरिक कार्ड धारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या भारत के दीर्घावधि वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या अवसन्नित हो चुका विदेशी पासपोर्ट; या

(viii) ऐसे फायदाग्राही के संबंध में जिसके पास कोई विधिक अभिभावक, दत्तक ग्रहण आदेश, या जिसके पास विधिक अभिभावकता सिद्ध करने वाला कोई अन्य दस्तावेज है, जो किसी विधि के न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (2016 का 49) और इन अधिनियमों के अधीन बने लागू नियमों और विनियमों के अनुसार जारी किया गया हो; या

(ix) कोई अन्य दस्तावेज, जिसे उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग विनिर्दिष्ट कर सके।

18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे फायदाग्राही जिन्हें आधार संख्या आवंटित नहीं की गई है:

(क) नामांकन केंद्र पर प्रचालक द्वारा फायदाग्राही के नामांकन प्रक्रिया से गुजरने की पावती, जिसमें नामांकन आईडी (ईआईडी) हो; और

(ख) इनमें से कोई भी एक दस्तावेज, जिस पर फायदाग्राही का फोटो हो, अर्थात्:—

(i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र;

(ii) राशन कार्ड;

(iii) जाति प्रमाण-पत्र या अधिवास प्रमाण-पत्र, जो किसी ऐसे राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो जो राज्य सरकार का कार्यकारी मजिस्ट्रेट या राजस्व अधिकारी हो और जिसका रैंक तहसीलदार के पद से कम का न हो;

(iv) किसी सरकारी संस्था या पब्लिक सेक्टर उद्यम द्वारा सेवानिवृत्त या सेवारत सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य को जारी किया गया मेडिकल या बीमा पहचान पत्र;

(v) भारतीय पासपोर्ट;

(vi) मान्यता प्राप्त स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक या 10^{वीं} कक्षा या उच्चतर माध्यमिक या 12^{वीं} कक्षा का प्रमाण-पत्र या अंक-पत्र;

(vii) किसी सरकारी अस्तित्व या पब्लिक सेक्टर उद्यम द्वारा सेवारत या सेवानिवृत्त लोक सेवक को जारी किया गया पहचान-पत्र या अन्य पहचान दस्तावेज;

(viii) 'दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017' के अधीन अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, या भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूडीआईडी कार्ड);

(ix) भारत में जारी चलन अनुज्ञप्ति:

(x) देखरेख और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालक या विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की दशा में, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अधीन इसके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन संबद्ध राज्य सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत बाल देखरेख संस्था में रखा गया है, ऐसी संस्था के प्रभारी, अधीक्षक, बाल कल्याण अधिकारी या परिवीक्षा अधिकारी द्वारा जारी जन्म की तारीख विनिर्दिष्ट करने वाला प्रमाण पत्र; या

(xi) किसी विदेशी नागरिक के संबंध में,—

(I) यदि वह भारत का विदेशी नागरिक कार्ड-धारक है, तो भारत का विदेशी नागरिक कार्ड;

(II) यदि वह तिब्बती शरणार्थी है, तो विदेशी क्षेत्रीय रजिस्ट्रीकरण कार्यालय द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र;

(III) यदि वह नेपाल या भूटान का नागरिक है, तो नेपाल या भूटान का पासपोर्ट;

(IV) यदि वह भारत का विदेशी नागरिक कार्ड धारक, तिब्बती शरणार्थी या नेपाल या भूटान के नागरिक से भिन्न है, तो या तो विदेशी पासपोर्ट के साथ भारतीय वीजा या भारत का दीर्घावधि वीजा या वर्तमान में विधिमान्य या अवसन्नित विदेशी पासपोर्ट; या

(xii) ऐसे फायदाग्राही के संबंध में जिसके पास कोई विधिक अभिभावक दत्तक ग्रहण आदेश, या जिसके पास विधिक अभिभावकता सिद्ध करने वाला कोई अन्य दस्तावेज है, जो किसी विधि के न्यायालय या सक्षम प्राधिकारी द्वारा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 (1890 का 8), किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015' (2016 का 2), राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निःशक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (1999 का 44) या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016' (2016 का 49) और उक्त अधिनियमों के अधीन बने लागू नियमों और विनियमों के अनुसार जारी किया गया हो; या

(xiii) कोई अन्य दस्तावेज, जिसे उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके:

(4) इस निमित्त उक्त सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा पदाभिहित कोई अधिकारी, खंड (3) के अधीन प्रस्तुत दस्तावेजों या उसकी अंतर्वस्तु में दी गई जानकारी को साबित करने वाले दस्तावेजों की जांच करेगा,—

(क) नामांकन आवेदन की प्रस्थिति जानने के लिए, myAadhaar पोर्टल (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) पर नामांकन आईडी (ईआईडी) प्रस्तुत करेगा ताकि यह पुष्टि हो जाए कि नामांकन आईडी (ईआईडी) और नामांकन आवेदन नामंजूर नहीं हुआ है; और

(ख) अन्य दस्तावेजों, और इस प्रयोजन के लिए, वे किसी सरकारी अस्तित्व या ऐसे प्राधिकारी की सहायता ले सकता है और उनके साथ दी गई जानकारी साझा कर सकता है, जो ऐसे दस्तावेजों में अंतर्विष्ट जानकारी को तैयार करने या अनुरक्षित करने का काम करता है।

2. फायदाग्राहियों द्वारा उक्त फायदों का सुविधाजनक रूप से उपभोग करने में मदद करने के लिए, मंत्रालय मीडिया के माध्यम से व्यापक पैमाने पर प्रचार सुनिश्चित करने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाएगा ताकि फायदाग्राहियों को उक्त स्कीम के अधीन आधार संख्या की अपेक्षा के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. किसी फायदाग्राही के आधार संख्या का बायोमेट्रिक-आधारित तरीकों (जैसे चेहरे की तस्वीर, उंगलियों के निशान या आइरिस स्कैन) से अभिप्रमाणन किसी कारण से जैसे बायोमेट्रिक जानकारी की खराब गुणवत्ता के कारण असफल हो जाता है, तो निम्नलिखित उपचारी क्रियाविधियां अपनाई जाएंगी: —

(क) अगर बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन का कोई विशिष्ट तरीका सफल नहीं होने की दशा में, बायोमेट्रिक-आधारित अधिप्रमाणन का कोई अन्य तरीका या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित अधिप्रमाणन का विकल्प दिया जाएगा, बशर्ते ऐसा करना संभव और अनुज्ञेय हो;

(ख) जिन मामलों में बायोमेट्रिक आधारित या वन-टाइम पिन (ओटीपी) आधारित तरीके से पहचान का अधिप्रमाणन करना संभव नहीं है, वहां यथास्थिति, आधार सिक्योर क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड या आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज, पर भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके आधार संख्या की वास्तविकता सुनिश्चित करने के पश्चात, निम्नलिखित में से किसी एक के आधार पर उक्त स्कीम का फायदा दिया जा सकता है:

(i) आधार कार्ड, आधार पत्र (जैसे कि, आधार संख्या बनने पर आधार संख्या धारक को जारी किया गया पत्र) या ई-आधार (जैसे कि, आधार पत्र की पासवर्ड-संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या mAadhaar ऐप से एक्सेस किया जा सकता है) को अंतर्विष्ट करने वाले सिक्योर क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) की आधार क्यूआर स्कैनर या mAadhaar ऐप का उपयोग करके क्यूआर कोड को स्कैन करके ऑफलाइन सत्यापन के माध्यम से इसकी वास्तविकता की पुष्टि की जाती है;

(ii) आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी दस्तावेज (जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है या इसके mAadhaar ऐप से एक्सेस किया जा सकता है) - जब तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) की वेबसाइट पर इस संबंध में दिए गए ब्यौरों के अनुसरण में इस प्रयोजन हेतु संबद्ध मंत्रालय या विभाग या स्कीम कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित एप्लिकेशन के माध्यम से इस दस्तावेज पर मौजूद भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के डिजिटल सिग्नेचर प्रमाण पत्र का ऑफलाइन सत्यापन करके इसकी वास्तविकता की पुष्टि न हो जाए।

4. इसमें उपर्युक्त अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी,—

(क) उक्त स्कीम के अधीन किसी बालक को फायदे से वंचित नहीं किया जाएगा—

(i) यदि वह अधिप्रमाणन के जरिए अपनी पहचान साबित करने या आधार नंबर होने का सबूत देने में असमर्थ रहता है; या

(ii) यदि उसे आधार नंबर नहीं दिया गया है किंतु नामांकन के लिए किया गया आवेदन प्रस्तुत करता है;

(ख) उक्त स्कीम के अधीन फायदा ऐसे बालक को उसकी पहचान सत्यापित करके और पैरा 1 के खंड (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट रीति में उसके माता-पिता या विधिक अभिभावक के साथ उसके संबंध का पता लगाकर दिया जाएगा; और

(ग) जहां खंड (ख) के अधीन फायदा दिया जाता है, वहां उसका अभिलेख रखा जाएगा, जिसकी समय-समय पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा समीक्षा और संपरीक्षा की जाएगी।

5. यह सुनिश्चित करने के लिए कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के वास्तविक फायदाग्राही को इस स्कीम के अधीन मिलने वाले फायदों से वंचित न रहना पड़े, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रत्यक्ष फायदा अंतरण मिशन के 19 दिसंबर, 2017 के कार्यालय ज्ञापन सं. डी-26011/04/2017-डीबीटी (जो <https://dbtbharat.gov.in> पर उपलब्ध है) में विनिर्दिष्ट अपवाद-निपटान क्रियाविधि का अनुसरण करेगा।

6. यह अधिसूचना, राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. V-11024/1/2026-एससीडी-I]

परवीन कुमार थिंद, संयुक्त सचिव

Ministry of Social Justice and Empowerment
(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th September, 2026

S.O. 5185(E).— Whereas, the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency;

And whereas, the Department of Social Justice and Empowerment (hereinafter referred to as the said Department) in the Government of India (hereinafter referred to as the said Government) is administering Top Class Education for Scheduled Castes (hereinafter referred to as the said scheme);

And whereas, scholarship (hereinafter referred to as the said benefit) is given to the Scheduled Caste Students (hereinafter referred to as the beneficiaries) under the said scheme and the instructions and guidelines issued in respect thereof;

And whereas, expenditure for the said scheme is incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, the said Department of Social Justice and Empowerment is desirous that the said Government, for the purpose of establishing identity of a beneficiary as a condition for the receipt of the said benefit, require that such beneficiary undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number or in the case of an individual to whom no Aadhaar number has been assigned, make an application for enrolment;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Government of India hereby notifies the following, namely: —

1. An individual desirous of availing of the said benefit under the said scheme shall be required to undergo authentication, or furnish proof of possession of Aadhaar number.

(2) In case such an individual has not been assigned an Aadhaar number, he shall be required to make an application for enrolment:

Provided that if that individual is a child, such application shall be made only with the consent of his parent or legal guardian.

(3) In accordance with the provisions of regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the said Department of Social Justice and Empowerment shall ensure enrolment of such beneficiaries who are yet to be enrolled, or update their Aadhaar details through appropriate measures, including coordination with Registrars and setting up enrolment centres at convenient locations or providing enrolment facilities by becoming a Registrar itself:

Provided that till such time an Aadhaar number is assigned to such beneficiary, he may establish his identity to avail of the said benefit, by presenting the following documents to which he is entitled and which are valid at the time of presentation, or, in case the software provided or authorised by the said Department of Social Justice and Empowerment for such identification supports electronic obtaining of information evidencing the contents of such documents from the database of the authorities dealing with the preparation or maintenance thereof, by giving his consent for so obtaining, namely:—

For a child below 18 years of age to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and

(b) any one of the following documents to evidence that the beneficiary is a child below 18 years of age, namely: —

(i) certificate of birth given under the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (18 of 1969), as extracted from the entry made in the register of births regarding the birth of the beneficiary;

(ii) Indian passport;

(iii) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;

(iv) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, Child Welfare Officer or probation officer of such institution; or

(v) in respect of a foreign national, —

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a long-term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(c) Any one of the following documents, having the photograph of the beneficiary, to evidence his relationship with the parent or legal guardian, namely: —

(i) ration card;

(ii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iii) medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(iv) Indian passport;

(v) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;

(vi) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, Child Welfare Officer or probation officer of such institution; or

(vii) In respect of a foreign national, —

(I) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(II) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(III) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(IV) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a long-term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(viii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999(44 of 1999) or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016(49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(ix) any other document as the said Department of Social Justice and Empowerment may specify, namely-

For beneficiaries aged 18 years or more to whom an Aadhaar number has not been assigned:

(a) the acknowledgement of the beneficiary having undergone the process of enrolment, provided by the operator at the enrolment centre, containing the Enrolment ID (EID); and

(b) any one of the following documents, having the beneficiary's photograph, namely: —

(i) Elector's Photo Identity Card issued by the Election Commission of India;

(ii) Ration card;

(iii) caste certificate or domicile certificate, issued by a Gazetted officer who is an Executive Magistrate or a revenue officer of the State Government, not below the rank of Tahsildar;

(iv) Medical or insurance identity card issued by a government entity or public sector enterprise to a retired or serving public servant or his family member;

(v) Indian passport;

(vi) certificate or statement of marks of matriculation or 10th class or higher secondary or 12th class, issued by a recognised Board of school education;

(vii) Identity card or other identity document issued to serving or retired public servant by a government entity or a public sector enterprise;

(viii) disability certificate issued by notified medical authority under Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, or Unique Disability Identification (UDID) card issued by the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Government of India;

(ix) driving licence issued in India;

(x) in respect of a child in need of care and protection or a child in conflict with law, who is housed by child care institution registered as such with the State Government concerned under the rules made by it under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015, certificate specifying his date of birth issued by the person-in-charge, superintendent, Child Welfare Officer or probation officer of such institution; or

(xi) in respect of a foreign national, —

(i) if he is an Overseas Citizen of India Cardholder, Overseas Citizen of India Card;

(ii) if he is a Tibetan refugee, registration certificate issued by a Foreigners Regional Registration Office;

(iii) if he is a national of Nepal or Bhutan, passport of Nepal or Bhutan;

(iv) if he is other than a Overseas Citizen of India Cardholder, Tibetan refugee or a national of Nepal or Bhutan, either an Indian visa along with foreign passport or a Long-Term Visa to India along with currently valid or expired foreign passport; or

(xii) in respect of a beneficiary who has a legal guardian, adoption order or other document to evidence legal guardianship, which is issued by a court of law or competent authority under the Guardians and Wards Act, 1890 (8 of 1890), the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (2 of 2016), the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999 (44 of 1999), or the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and the applicable rules and regulations made under the said Acts; or

(xiii) any other document as the said Department of Social Justice and Empowerment may specify.

(4) An officer designated by the said Department of Social Justice and Empowerment in this behalf shall check in respect of the documents presented or the information evidencing the contents thereof under clause (3), —

(a) the status of the enrolment request by submitting the Enrolment ID (EID) on myAadhaar portal (<https://myaadhaar.uidai.gov.in/portal>) to confirm that the Enrolment ID (EID) and that the enrolment request does not stand rejected; and

(b) the other documents, and for this purpose, may take the assistance of and share the information presented with any government entity or an authority that deals with the preparation or maintenance of the information contained in such documents.

2 In order to enable beneficiaries to avail of the said benefits conveniently, the Ministry shall make all necessary steps to ensure wide publicity through media to make the beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar number under the said scheme.

3 Where the authentication of the Aadhaar number of a beneficiary done through any of the biometric-based modes of authentication (namely, facial image, fingerprints or iris scan-based authentication) fails due to any reason, such as poor quality of biometric information, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely: —

(a) in case any particular biometric-based mode of authentication is not successful, any other mode of biometric-based authentication or one-time pin (OTP) based authentication shall, wherever feasible and admissible, be offered;

(b) in cases where biometric-based or one-time pin (OTP) based modes of authentication are not possible, benefits under the said scheme may, after establishing the genuineness of the Aadhaar number by doing offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority of India (UIDAI) on the Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code or the Aadhaar Paperless Offline e-KYC document, as the case may be, be given on the basis of any of the following: -

(i) an Aadhaar Secure Quick Response (QR) Code containing Aadhaar card, Aadhaar letter (i.e., the letter issued to an Aadhaar number holder on generation of his Aadhaar number) or e-Aadhaar (i.e., the password-protected electronic copy of Aadhaar letter downloadable from the website of Unique Identification Authority (UIDAI) or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification by scanning the QR code using the Aadhaar QR Scanner or mAadhaar apps;

(ii) Aadhaar Paperless Offline e-KYC document (downloadable from the website of Unique Identification Authority (UIDAI) or accessible using its mAadhaar app), after its genuineness is established through offline verification of the digital signature certificate of Unique Identification Authority (UIDAI) on the document through the application developed by the Ministry or Department or scheme implementing agency concerned for this purpose, in accordance with the details given in this regard on the website of Unique Identification Authority (UIDAI).

4 Notwithstanding anything contained hereinabove, —

(a) benefit under the said scheme shall not be denied to a child, —

(i) in case of failure to establish his identity by undergoing authentication or to furnish proof of possession of Aadhaar number; or

(ii) in case of production of an application for enrolment where he has not been assigned an Aadhaar number;

(b) benefit under the said scheme shall be given to such a child by verifying his identity and establishing his relationship with his parent or legal guardian in the manner specified in the proviso to clause (3) of paragraph 1; and

(c) where benefit is given under clause (b), a record shall be maintained in respect of the same, which shall be reviewed and audited periodically by the Department of Social Justice and Empowerment.

5 In order to ensure that *bona fide* beneficiaries who are aged 18 years or more are not deprived of the benefit due to them under the said scheme, the Department of Social Justice and Empowerment shall follow the exception handling mechanism specified in the Office Memorandum no. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December, 2017 of the Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India (available on <https://dbtbharat.gov.in>).

6 This notification shall come in force from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. V-11024/1/2026-SCD-I]

PARVEEN KUMAR THIND, Jt. Secy.